

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 488

दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

सशस्त्र सीमा बल का आधुनिकीकरण

488. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को आधुनिक बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ड्रोन, ड्रोन-रोधी तकनीक, थर्मल इमेजिंग उपकरण और आधुनिक संचार उपकरण जैसी अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) एसएसबी के लिए जारी और प्रस्तावित आधुनिकीकरण पहलों के कब तक पूरा होने की अपेक्षा है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान एसएसबी के आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास के लिए आवंटित की गई और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत एसएसबी के कार्यबल, प्रशिक्षण और प्रचालन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य नियत किए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): सशस्त्र सीमा बल ने आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए, निगरानी और बल के आधुनिकीकरण के लिए मानव रहित विमान, मानव रहित माइक्रो विमान, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, ऑटोमैटिक फेसरिकग्रिशन सिस्टम एवं ऑटो नंबर प्लेट रिकग्रिशन के साथ सीसीटीवी निगरानी प्रणाली तथा सैटेलाइट फोन खरीदे हैं।

उपरोक्त के अलावा, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए आधुनिकीकरण योजना को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य हथियारों, संचार, सुरक्षात्मक गियर, निगरानी और सीमा रक्षा प्रणालियों, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक वस्तुओं, बख्तरबंद वाहनों और विशेष परिवहन वाहनों हेतु नवीनतम और अत्याधुनिक उपकरणों को शामिल करके क्षमता वृद्धि से प्रत्येक सीएपीएफ की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार करना है।

(ख): बलों का आधुनिकीकरण तथा नवीनतम और अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद एक सतत प्रक्रिया है।
अतः इस उद्देश्य से विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

(ग): आधुनिकीकरण और बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित पिछले दस वर्षों अर्थात् वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक के दौरान सशस्त्र सीमा बल को 5001.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और उसमें से अब तक 4775.11 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष के पूरा होने अर्थात् दिनांक 31.03.2026 तक और अधिक धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

वर्ष 2013 से लेकर वर्तमान में चल रही आधुनिकीकरण योजना-IV के दौरान दिनांक 31.03.2026 तक, सशस्त्र सीमा बल को आधुनिकीकरण योजना-II, III और IV के तहत 241.15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और हथियार, संचार, सुरक्षात्मक गियर, निगरानी और सीमा सुरक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक वस्तुओं, बख्तरबंद वाहनों और विशेष परिवहन वाहनों हेतु विभिन्न प्रकार के नवीनतम और अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 210.02 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(घ): मानव संसाधन की आवश्यकता और क्षमता निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है और इसलिए इस संदर्भ में कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं रखा गया है। इसका आकलन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और उसी के अनुसार इसे प्रदान किया जाता है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के संख्या बल को मजबूत करने के लिए (i) भर्ती नियमों के अनुसार समय पर डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति कोटा के तहत रिक्तियों को भरा जाता है (ii) सीधी भर्ती के पदों को अधिसूचित किया जाता है और एसएससी/यूपीएससी/एमओएसबी/विभाग के माध्यम से भरा जाता है (iii) गैर-जीडी कैडरों के पदों को भरने के लिए आंतरिक भर्ती समय पर की जाती है और (iv) कुछ रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाता है।

इसके अलावा, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बल की आवश्यकतानुसार और जब भी बल द्वारा नवीनतम और अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त किए जाते हैं, बल के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि बल की परिचालन (ऑपरेशनल) क्षमता बढ़ाई जा सके। एसएसबी ने अपने कार्मिकों को ड्रोन डेस्टिनेशन गुरुग्राम (हरियाणा), जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान है, में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण लेने के लिए, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में विशेष संचार उपकरण प्रशिक्षण के लिए और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी भेजा है। ये आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बल की परिचालन क्षमता को मजबूत करेंगे।